RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 07 OCTOBER TO 13 OCTOBER 2020 प्रति बुधवार वर्ष 06 अंक 7 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

कार, तंबाकू, लग्जरी वस्तुओं पर जून 2022 के बाद भी 28% जीएसटी के अलावा लगता रहेगा उपकर Page 2

ज़नसोलर के सोलर प्रोडक्ट की विस्तृत रेंज से अब हर घर होगा रोशन Page 3

कंटेनर की उपलब्धता नहीं होना निर्यात क्षेत्र के लिये वर्तमान में एक चुनौती Page 5

editoria!

बढ़त के संकेत

भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतरी के शुरुआती संकेत मिलना न केवल सुखद, बल्कि उत्साहजनक भी है। किसी भी अर्थव्यवस्था में कर संग्रह की घटत या बढ़त से एक अंदाजा लगता है। स्वाभाविक ही ज्यादा व्यवसाय होने पर ज्यादा कर संग्रह की गुंजाइश बनती है और विशेष रूप से जीएसटी की जो व्यवस्था है, उसमें कर चोरी बहुत आसान नहीं है, अतः अगर जीएसटी संग्रह में सितंबर में सुधार दिख रहा है, तो यह पूरे देश के लिए उम्मीद जगाने वाली बात है। यह खुशी तब और ज्यादा हो जाती है, जब हम पलटकर पिछले पांच महीनों के आंकड़ों को देखते हैं। अप्रैल में जीएसटी संग्रह बुरी तरह प्रभावित हुआ था, संग्रह में पिछले साल की तुलना में 71.75 प्रतिशत की कमी आई थी। मई से सुधार का क्रम शुरू हुआ, पर जुलाई ने हमें निराश किया था, जून में जहां 9.03 प्रतिशत की गिरावट हुई थी, वहीं जुलाई में यह 14.36 प्रतिशत गिर गई थी। मतलब स्थिति में सुधार की बजाय बिगाड़ के संकेत दिखने लगे थे। लेकिन अब सितंबर में जो 3.88 प्रतिशत की बढ़त दिखाई जा रही है, उससे अर्थव्यवस्था के तमाम अंगों को बेहतर प्रदर्शन का जरूरी उत्साह हासिल होगा। अगस्त से अगर तुलना करें, तो सितंबर में जीएसटी संग्रह में 10.4 प्रतिशत की बढ़त मायने रखती है। आज कोरोना के दौर और अनलॉक होते देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार सबसे जरूरी है। साथ ही, फैक्टरियों में उत्पादन बढ़ने का क्रम शुरू हो गया है। विनिर्माण के आंकडे भी गवाह हैं, सितंबर में लोगों ने स्थानीय स्तर पर खूब खरीद की है, साथ ही, निर्यात में भी बढ़त लौटी है। मैन्युफैक्चरिंग का पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) सितंबर में 56.8 पर पहुंच गया है। जनवरी 2012 के बाद यह सबसे अच्छी स्थिति है। हालांकि अभी आंकड़ों पर हमें बहुत फिदा नहीं होना चाहिए। अभी उद्धार की बहुत गुंजाइश है। अर्थव्यवस्था के पुराने औजारों को पूरी तरह से सक्रिय करने के साथ ही जो नए निवेश और नवाचार हैं, उन्हें युद्ध स्तर पर उत्पादक बनाने की जरूरत है। कोरोना के समय जो गिरावट देश झेल चुका है, न केवल उसकी भरपाई, बल्कि कोरोना से पहले चल रही आर्थिक सुस्ती से लगी चोटों का भी हमें उपचार करना है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अनलॉक होना हमारी मजबूरी भी है। अनलॉक पांच की प्रक्रिया चल रही है। इस चरण में 15 अक्तूबर से सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क भी खुल जाएंगे। इसके बाद स्कूलों को भी खोलने के निर्देश हो गए हैं। अब राज्य सरकारों को अपने स्तर पर जरूरत के हिसाब से फैसले लेने हैं। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेंगी। साफ है, सरकार सामान्य जीवन और जीविका की वापसी के लिए दृढ़ है। हां, जीविका को जीवन से थोड़ी ज्यादा तरजीह देने की बात कही जा सकती है, लेकिन इससे अच्छा क्या उपाय हो सकता है? लोगों को अपने स्तर पर ही सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यक्तिगत सावधानी के दिशा-निर्देश बार-बार दोहराए गए हैं, जिनकी पालना सरकार को भी सुनिश्चित करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को पहले की तुलना में दोगुनी परिवहन सुविधा के साथ अर्थव्यवस्था को बल देना चाहिए। इसके साथ ही, समाज के जिन तबकों और लोगों को राहत देना जरूरी है, उनके साथ खड़े होना भी सुधार का हिस्सा है।

भारत एक दिन में 4.1 करोड़ रियल टाइम वित्तीय लेन-देन के साथ दुनिया में अग्रणीः रिपोर्ट

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में दैनिक रियल टाइम वित्तीय लेन-देन 4.1 करोड़ पर पहुंच गया है। यह विश्व में सर्वाधिक है तथा साल भर पहले की तुलना में दो गुना से अधिक है। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गयी। दुनिया भर में व्यापारियों, बैंकों और पूंजी बाजारों को प्रौद्योगिकी समाधान मुहैया कराने वाली कंपनी एफआईएस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में दैनिक रियल टाइम लेन-देन साल भर पहले की तुलना में दो गुना से अधिक होकर 4.1 करोड़ पर पहुंच गया है। बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, छह अन्य

देशों में भी दैनिक रियल टाइम लेन-देन इस दौरान दो गुना से अधिक हुआ है। इनके अलावा चार देशों में कम से कम दो गुना वृद्धि हुई है। हालांकि वृद्धि दर के हिसाब से बहरीन शीर्ष पर रहा है। बहरीन में दैनिक रियल टाइम वित्तीय लेन-देन की वृद्धि दर 657 प्रतिशत रही है। इसके बाद 488 प्रतिशत के साथ घाना, 309 प्रतिशत के साथ फिलीपींस, 214 प्रतिशत के साथ ऑस्ट्रेलिया और 208 प्रतिशत के साथ पोलैंड का स्थान रहा है। भारत में यह दर 213 प्रतिशत रही है। प्रति व्यक्ति रियल टाइम लेन-देन के मामले में दैनिक 75 भुगतान के साथ दक्षिण कोरिया शीर्षपर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में अभी 130 वित्तीय संस्थान रियल टाइम भुगतान की सुविधा दे रहे हैं। यह सितंबर 2019 की तुलना में पांच गुना की वृद्धि है।

सरकार ने गैस बेचने की दी छूट

रिलायंस अन्य अपनी सहयोगी कंपनियों को बेच सकेंगी गैस

नई दिल्ली। एजेंसी

गैस क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुये सरकार ने बुधवार को बिना नियमन वाले क्षेत्रों से निकलने वाली गैस को बेचने की पूरी तरह से छूट दे दी। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को फायदा होगा और वह अपनी सहयोगी कंपनियों को गैस की बिक्री कर सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गैस मूल्य की खोज के लिये एक मानक इलेक्ट्रानिक- बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। सरकार ने 2016 से लेकर 2019 के बीच सभी क्षेत्रों को मूल्य तय करने की आजादी दे दी थी। हालांकि, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (आयल) को नामांकन आधार पर दिये गये क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। मूल्य निर्धारण की आजादी दी गई लेकिन गैस बिक्री को लेकर कई तरह के प्रतिबंधों को जारी रखा गया। गैस उत्पादक उससे जुड़ी सहयोगी कंपनियों को गैस की बिक्री नहीं कर सकते थे और कई मामलों में तो सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी को ही गैस उठाने को प्राधिकृत कर दिया गया था। इससे प्रतिस्पर्धा में रुकावट आई और दाम भी कृत्रिम रूप से नीचे रहीं । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धमेन्द्र प्रधान ने यहां सेवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने प्राकृतिक गैस विपणन के क्षेत्र में सुधारों को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि इससे ओएनजीसी और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उन्हें नामांकन आधार पर दिये गये गैस क्षेत्रों से निकलने वाली गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा। इनके लिये हाल ही में 1.79 डालर प्रति इकाई (प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट) की दर तय की गई है। उन्होंने कहा कि सीसीईए ने पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ई- बोली के जरिये गैस का मूल्य खोज निकालने के लिये एक मानक प्रक्रिया को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही गैस उत्पादक कंपनी की सहायक इकाइयों को भी बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी। जिन गैस क्षेत्रों के उत्पादन भागीदारी अनुबंध (पीएससी) में गैस विपणन की पूरी आजादी का प्रावधान किया गया है उन क्षेत्रों से निकलने वाली गैस की मार्केटिंग को पूरी आजादी दी गई है। इससे वेदांता के स्वामित्व वाली केयर्न और फोकस एनर्जी जैसी कंपनियों को फायदा होगा। ये कंपनियां अब किसी को भी गैस की बिक्री कर सकेंगी। प्रधान ने कहा कि प्राकृतिक गैस विपणन क्षेत्र में किये गये इस सुधार से गैस के मौजूदा 8.40 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) में 4 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन उत्पादन को और जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गैस उत्पादक कंपनी द्वारा खुद की गैस को खरीदने के मामले पर रोक जारी रहेगी ताकि इसमें किसी तरह का एकाधिकार नहीं हो सके। हालांकि, इन कंपनियों की अनुषंगी कंपनियों को गैस मूल्य खोज के लिये होने वाली नीलामी में बोली लगाने की अनुमति होगी। पिछले साल ही रिलायंस और उसकी भागीदारी बीपी ने अपने केजी-डी6 ब्लॉक से 50 लाख घनमीटर गैस प्रतिदिन की बोली निकाली थी जिसमें एस्सार और जीएसपीसी सफल रहीं। हालांकि, रिलायंस और बीपी खुद इस गैस को खरीदने के लिये तैयार थी लेकिन नियमों के तहत वह ऐसा नहीं कर पाये। अब रिलायंस और बीपी का संयुक्त उद्यम इंडिया गैस साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गैस बिक्री में बाली लगाने और खरीदारी करने की हकदार होगी।

सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी जबरदस्त मंदी

नई दिल्ली। एजेंसी

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। सर्राफा बाजार में सोना अपने ऑल टाइम हाई 57,008 रुपये से 6,643 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी सात अगस्त के अपने उच्च शिखर से 18928 रुपये तक टूट चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दिवाली तक सोना काफी सस्ता हो जाएगा।

सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी जबरदस्त मंदी

देशभर के सर्राफा बाजारों में सोना सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी का भाव 2,000 रुपये कम हुआ। आज 7 अक्टूबर को देशभर के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 679 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर खुला। आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 50365 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी के रेट में आज 2,011 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई और चांदी का हाजिर भाव 59,021 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

कार, तंबाकू, लग्जरी वस्तुओं पर जून 2022 के बाद भी 28% जीएसटी के अलावा लगता रहेगा उपकर

नई दिल्ली। एजेंसी

जीएसटी परिषद ने सोमवार (05 अक्टूबर) को कार और तंबाकू जैसे उत्पादों पर उपकर जून 2022 के बाद भी लगाने का निर्णय किया। लेकिन परिषद राज्यों को कर राजस्व के नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति के उपायों पर आम सहमति बनाने में विफल रही। परिषद की करीब आठ घंटे चली बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने कहा कि क्षतिपूर्ति के मामले में विचार के लिए परिषद की 12 अक्टूबर को फिर बैठक होगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। जीएसट के प्रभाव में आने के बाद यह कर की दरों और ढांचे के बारे में निर्णय करती है। परिषद राजनीतिक विचारों के आधार पर बटी नजर आयी। जहां गैर-भाजपा शासित और उसको समर्थन देने वाले दलों ने केंद्र के राजस्व में कमी की भरपाई कर्ज लेकर करने के प्रस्ताव का विरोध किया। ऐसा लगता है कि राज्य क्षतिपूर्ति का मामला परिषद में मतदान की ओर बढ़ रहा है। जो विकल्प अधिक संख्या में राज्य चुनेंगे, उसे लागू किया जाएगा। जीएसटी जब जुलाई 2017 में पेश किया गया था, राज्यों से उनकी अंतिम कर प्राप्ति के हिसाब से माल एवं सेवा कर लागू होने के पहले पांच साल तक 14 प्रतिशत की दर से राजस्व में वृद्धि का वादा किया गया था। इसमें कहा गया था कि किसी प्रकार की कमी की भरपाई केंद्र आरामदायक और समाज के नजरिये अहितकर वस्तुओं पर उपकर लगाकर करेगा। केंद्र ने राजस्व में कमी को पूरा करने के लिये यह सुझाव दिया है कि राज्य भविष्य में होने वाले क्षतिपूर्ति प्राप्ति के एवज में कर्ज ले सकते हैं।

बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि 21 राज्यों ने कर्ज लेने के विकल्प को चुना है। लेकिन वह अन्य राज्यों के बीच सहमति बनाने को लेकर क्षतिपूर्ति के वित्त पोषण को लेकर और चर्चा करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य चाहते हैं कि केंद्र जीएसटी संग्रह में कमी का आकलन 97,000 करोड़ रुपए के बजाए 1.10 लाख करोड़ रुपए करे। इस पर केंद्र ने परिषद की 42 वीं बैठक से पहले सहमति व्यक्त की थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्र ने अगस्त में चालू वित्त वर्ष में राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में 2.35 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की कमी का अनुमान लगाया। केंद्र के आकलन के अनुसार करीब 97,000 करोड़ रुपए की कमी जीएसटी क्रियान्वयन के कारण है, जबकि शेष 1.38 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की वजह कोविड-19 है। इस महामारी के कारण राज्यों के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

केंद्र ने इस कमी को पूरा करने राज्यों को दो विकल्प दिये हैं। इसके तहत 97,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली विशेष सुविधा से या पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपए बाजार से लेने का विकल्प दिया गया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के लिये आरामदायक और अहितकर वस्तुओं पर उपकर 2022 के बाद भी लगाने का प्रस्ताव किया था। गैर-भाजपा शासित राज्य केंद्र के राजस्व संग्रह में कमी के वित्त पोषण के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। छह गैर-भाजपा शासित राज्यों...पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ने केंद्र को पत्र लिखकर विकल्पों का विरोध किया जिसके तहत राज्यों को कमी को पूरा करने के लिये कर्ज लेने की जरूरत है।

सीतारमण ने कहा कि सवाल यह है कि 20 राज्यों ने पहला विकल्प चुना है लेकिन कुछ राज्यों ने कोई विकल्प नहीं चुना। जिन राज्यों ने विकल्प नहीं चुना है, उनकी दलील है कि केंद्र को कर्ज लेना चाहिए। यह महसूस किया गया कि आप 21 राज्यों की तरफ से निर्णय नहीं कर सकते जिन्होंने आपको पत्र लिखा है। हमें इस बारे में और बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे यह भी याद दिलाया गया कि आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकती। मैंने इस पर वहां कहा और यहां कह रही हूं कि किसी को भी हल्के में नहीं लेती। मैंने वहां कहा और यहां भी कह रही हूं कि मैं हमेशा बातचीत और चर्चा के लिये तैयार रहती हूं। परिषद की बैठक फिर 12 अक्टूबर को होगी।

कर्ज लौटाने के बारे में सीतारमण ने कहा कि उधार ली गयी राशि पर ब्याज का सबसे पहले भुगतान उपकर से किया जाएगा जिसका संग्रह पांच साल के बाद भी होगा। उसके बाद कर्ज ली गयी 1.10 लाख करोड़ रुपए की मूल राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत का भुगतान कोविड प्रभावित क्षतिपूर्ति के लिये किया जाएगा।

डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर खुला

नई दिल्ली। एजेंसी

डॉलर के मुकाबले रुपया आज बुधवार यानी 7 अक्टूबर 2020 को कमजोरी के साथ खुला। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे की कमजोरी के साथ 73.55 रुपये के स्तर पर खुला। वहीं, मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की कमजोरी के साथ 73.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।

जानिए पिछले 5 दिनों के रुपये का क्लोजिंग स्तर

■मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की कमजोरी के साथ 73.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। ■सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे की कमजोरी के साथ 73.29 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। ■गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 62 पैसे की मजबूती के साथ 73.14 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। ■बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की मजबूती के साथ 73.76 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। ■मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की कमजोरी के साथ 73.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।

आजादी के समय रुपये का स्तर

एक जमाना था जब अपना रुपया डॉलर को जबरदस्त टक्कर दिया करता था। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो डॉलर और रुपये का दाम बराबर का था। मतलब एक डॉलर बराबर एक रुपया था। तब देश पर कोई कर्ज भी नहीं था। फिर जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो सरकार ने विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया और फिर रुपये की साख भी लगातार कम होने लगी। 1975 तक आते-आते तो एक डॉलर की कीमत 8 रुपये हो गई और 1985 में डॉलर का भाव हो गया 12 रुपये। 1991 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत ने उदारीकरण की राह पकड़ी और रुपया भी धड़ाम गिरने लगा।

डिमांड सप्लाई तय करता है भाव

करेंसी एक्सपर्ट के अनुसार रुपये की कीमत पूरी तरह इसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी इस पर असर पड़ता है। हर देश के पास उस विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, जिसमें वो लेन-देन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। अमरीकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है और ज्यादातर देश इंपोर्ट का बिल डॉलर में ही चुकाते हैं।

पहली वजह है तेल के बढ़ते दाम

रुपये के लगातार कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल के बढ़ते दाम हैं। भारत कच्चे तेल के बड़े इंपोर्टर्स में एक है। भारत ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और इसका बिल भी उसे डॉलर में चुकाना पड़ता है।

दूसरी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजारों में अक्सर जमकर बिकवाली करते हैं। जब ऐसा होता है तो रुपये पर दबाव बनता है और यह डॉलर के मुकाबले टूट जाता है।

लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स

RIL में करीब 3% की बढ़त

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

लगातार चार दिन की बढ़त के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती देखने को मिली। हालांकि, कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स में 304 अंक की तेजी रही. बाजार में अच्छी स्थिति रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और इन्फोसिस में तेजी के साथ शेयर बाजार में मजबूती आयी. तीस शेयरों वाला सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला। लेकिन बाद में इसमें तेजी आयी और अंत में 304.38 अंक यानी 0.77 प्रतिशत मजबूत होकर 39,878.95 अंक पर बंद हुआ।

इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76.45 अंक यानी 0.66 प्रतिशत मजबूत होकर 11,738.85 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में एनएसई निफ्टी 76.45 यानी 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,738.85 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में टाइटन रही। इसमें 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी आयी। इसके अलावा बजाज ऑटो, मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी तेजी रही। दूसरी तरफ, जिन शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी, उनमें बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड, टाटा स्टील, एनटीपीसी और सन फार्मा शामिल थे। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 3 फीसदी से ज्यादा की बढ़त रही। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. ने अबु धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) से 5,512.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी अबतक चार सप्ताह से भी कम समय में 37,710 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

मंगलवार को थी रौनक

बीते मंगलवार को तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 600.87 अंक यानी 1.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 39,574.57 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 159.05 अंक यानी 1.38 प्रतिशत मजबूत होकर 11,662.40 अंक पर ठहरा। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में बाजार में अच्छी दखल रखने वाली कंपनी एचडीएफसी में 8.35 प्रतिशत की तेजी आयी। लाभ में रहने वाले प्रमुख शेयरों में इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल हैं। दूसरी तरफ टाटा स्टील, नेस्ले, लार्सन एंड टूब्रो, सन फार्मा, एनटीपीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट दर्ज की गयी।

ज़नसोलर के सोलर प्रोडक्ट की विस्तृत रेंज से अब हर घर होगा रोशन

zunsolar
अपना solar

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

आज गाँवों में भी बिजली के बिल कमर तोड़ रहे है, बिल के कारण कई परिवार अँधेरे में गुजर-बसर करने को मजबूर है। गरीब आदमी अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए खून-पसीना एक कर देता है, ऐसे में 4-4 हजार तक के बिजली बिल को भर पाना उनके लिए असंभव होता जा रहा है। ज़नसोलर किफायती रेंज में सोलर कॉम्बो के तहत कई सोलर प्रोडक्ट लेकर आया है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य ँइ्र कार्ड धारकों और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को भारी-भरकम बिजली के बिल से मुक्ति दिलाना और हर घर तक रौशनी पहुँचाना है।

ज़नरूफ़ के अंतर्गत ज़नग्रिड 2001 , ज़नग्रिड 3001 , ज़नग्रिड 4001 , ज़नग्रिड 5001 जैसे कई कॉम्बो मौजूद है. कॉम्बो में विभिन्न कॉम्बिनेशन में सोलर पैनल, सोलर बैटरी, सोलर इनवर्टर, सोलर मैनेजमेंट यूनिट्स, सोलर चार्ज कंट्रोलर्स, एमसी 4 कनेक्टर, डीसी वायर्स जैसे प्रोडक्ट्स की एक विस्तृत रेंज शामिल है।

ये कॉम्बो स्ट्रीट लाइटिंग, मोबाइल चार्जिंग के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और इसके अलावा अन्य डीसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे 2 डीसी बल्ब, डीसी टीवी और डीसी फैन आदि संचालित कर सकते हैं। सोलर कॉम्बो को कम से कम 8 घंटे से लेकर अधिकतम 24 घंटे तक संचालित किया जा सकता है, इसके लिए बड़े स्थानों की जरुरत भी नहीं होती है और इन्हे आसानी से छोटे क्षेत्रों या घरों में फिट किया जा सकता है। ज़ूनसोलर की किफायती कॉम्बो रेंज का ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष महत्व हो सकता है और इसका उपयोग किसान कर सकते हैं- वह अपने घर में टीवी और पंखा चला सकते हैं, सब्जी विक्रेता दिन में अपने मोबाइल फोन चार्ज कर सकते है. छोटे ग्रामीण विक्रेताओं से अपनी दुकानों में एक बल्ब, एक पंखा या एक टीवी आदि आसानी से चला सकते हैं। इसी प्रकार, इन कॉम्बो का उपयोग ग्रामीण वाहन गैरेज, छोटे शहर के गोदामों, ग्रामीण इलाकों, दुकानों या घरों में या जहां बिजली नहीं रहती इन प्रोडक्ट्स द्वारा खुशियों की रौशनी फैला सकते है।

कंपनी के फाउंडर और सी.ई.ओ श्री प्रणेश चौधरी ने कहा ' आम आदमी आज पहले से ही सीमित आय की समस्या से जूझ रहा है. आज उसके लिए अपने परिवार का पेट भरना और अन्य खर्चों का एक साथ भार उठाना उसके लिए मुश्किल होते जा रहा है. आज भी देश के कुछ गावों में बिजली कटौती की समस्या आम बनी हुई है. इसलिए ज़नसोलर में हम इन तकलीफों को ध्यान में रखते हुए बजट में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन मुहैया करा रहे है. अब मजदुर हो या किसान देश का कोना-कोना रोशन होगा. हमारा सपना है, देश का हर घर हो प्रकृति से रोशन- इसलिए हमारा फोकस नए और किफायती सोलर प्रोडक्ट पर है.' देश के कई मजदुर और किसान ज़नसोलर के प्रोडक्ट से न सिर्फ संतुष्ट है बल्कि बढे हुए बिजली बिल से छुटकारा पाकर खुश भी है. हर घर हो रोशन इस मशाल को लिए ज़नसोलर आम आदमी को 20 एम्पेयर चार्ज

कंट्रोलर, 20 एम्पेयर बैटरी और 50 सौर पैनल का कॉम्बो सिर्फ 6500 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ अपना घर रोशन करने का मौका दें रहा है.

बिजली की उपलब्धता एक आम आदमी की बुनियादी जरूरत है, इस बात को समझते हुए ज़नरूफ़ टेक ने कई सोलर प्रोडक्ट्स और कॉम्बो के साथ किफायती रेंज में ज़नसोलर को लॉन्च किया हैं और इसका उपयोग उन स्थानों पर बिजली प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जहां पर कई कारणों से पूरे दिन बिजली उपलब्ध नहीं होती है। सोलर पावर जैसे एनर्जी के एक नए स्रोत के साथ आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने 205 मेगावाट ऑपरेटिंग सोलर परिसंपत्तियों का अधिग्रहण पूरा किया

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने आज एस्सेल ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (ईजीईपीएल) और एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईआईएल) से 205 मेगावाट की ऑपरेटिंग सोलर संपत्ति का अधिग्रहण पूरा करने की घोषणा की। ये परिसंपत्तियां पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सभी परिसंपत्तियों के विभिन्न राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) हैं। पोर्टफोलियो लगभग 21 वर्षों के औसत शेष पीपीए जीवन के साथ अभी युवा है। अधिग्रहित परिसंपत्ति का 100% स्वामित्व अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग टेन लिमिटेड के पास रहेगा, जो एजीईएल की 100% सहायक कंपनी है। यह अधिग्रहण एजीईएल द्वारा अधिग्रहित किया गया पहला ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो अधिग्रहण है। एजीईएल ने पहले 29 अगस्त 2019 को एस्सेल पोर्टफोलियो के अधिग्रहण के लिए निश्चित समझौतों के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विनीत जैन ने बताया कि '205 मेगावाट के सोलर पोर्टफोलियो के अधिग्रहण से उन राज्यों में हमारी उपस्थिति का विस्तार हुआ है, जहां हम पहले से ही मौजूद हैं, और हम अपनी मजबूत परिचालन विशेषज्ञता के साथ, हम अपने शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण वैल्यू प्रदान करेंगे। यह 2025 तक अक्षय ऊर्जा के 25 गीगावॉट के लक्षित फुटप्रिंट के करीब एजीएल को ले जाने की दिशा में एक और कदम है।'

भारत के पास सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनने का अवसरः कांत

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण सरकार द्वारा घोषित रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है और भारत के पास इस क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनने का अवसर है। 'इंडिया पीवी एज 2020: रि-डिफाइन व्हाट इज पॉसिबल' पर 'ऑनलाइन' सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि सरकार को खासकर उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण का भरोसा है। उन्होंने कहा, ''सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) विनिर्माण रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है, जिसकी घोषणा सरकार ने कोविड-19 चुनौतियों के बीच आत्मनिर्भर भारत पुनरूद्धार पहल के तहत की है। भारत को सौर पीवी विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं।'' नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि बड़ा बाजार और जरूरी विनिर्माण संबंधी लाभ के साथ भारत अत्याधुनिक पूरे मूल्य श्रृंखला में पीवी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े स्तर पर विनिर्माण गंतव्य बन सकता है। उन्होंने कहा, ''हम इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां भारत के पास सौर पीवी विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र होने का अवसर है और विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को लेकर भरोसा है।'' कांत ने उम्मीद जतायी कि पीवी प्रौद्योगिकी में सुधार, बाजार उम्मीदों से अधिक होगा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की लागत में कमी लाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भारत में 31,000 मेगावाट मांग है। इसके लिये स्थानीय रूप से विनिर्मित सौर पैनलों की जरूरत है। यही अगले 10 साल में 3,000,00 मेगावाट का बड़ा लक्ष्य है। कुमार ने पीवी विनिर्माण करने वाले उद्योग से इस बड़े मांग का उपयोग कर अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा में निवेश करने और सौर पैनल के प्रदर्शन को निरंतर बेहतर बनाने तथा लागत में कमी लाने को लेकर स्टार्ट-अप तथा शोध संस्थानों के साथ गठजोड़ का आग्रह किया। आधिकारिक बयान के अनुसार सौर पीवी विनिर्माण उन रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की है। सरकार देश में हर गांवों में खासकर कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिये निरंतर प्रयास कर रही है।

अदाणी ने रॉयल्टी समझौते की घोषणा का जवाब दिया

अदाणी के प्रवक्ता की तरफ से दिया गया बयान

नई दिल्ली। एजेंसी

गुरुवार 1 अक्टूबर को दिए गए क्वींसलैंडट्रेजरर की टिप्पणियों के साथ एकरूपता जाहिर करते हुए, हम पुष्टि कर सकते हैं कि रॉयल्टी समझौते पर अदाणी और पलासजुक सरकार दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। कारमाइकल प्रोजेक्ट से खनन संबंधी करों और रॉयल्टी में अरबों की बढोत्तरी होगी, जो परिचालन के शुरुआती 30 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई और क्वींसलैंड सरकारों को प्राप्त होगी। यह धनराशि क्वींसलैंडमें स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण में मदद करेगी। खदान और रेल का निर्माण सुचारू रूप से जारी है, जिसमें 1,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है और कारमाइकल प्रोजेक्ट को मिले अनुबंधों में 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। हमारे 88ड्ड से अधिक अनुबंध क्वींसलैंड में कार्यान्वित किए जा रहे हैं और राज्य के सभी दिशाओं में फैले हुए हैं, ताकि हमारी परियोजना से लाभान्वित होने का अवसर अधिक से अधिक क्षेत्रों को मिल सके, और साथ ही, हम उच्च कौशल वाले निर्माण कार्य और क्वींसलैंड के संसाधन उद्योग के कार्यबल में भी अवसरों का लाभ ले सकें। खनन ने क्वींसलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्थाओं को कोविड-19 लॉकडाउन के सबसे विनाशकारी आर्थिक प्रभावों से बचाया है और हमें इसका हिस्सा बनने पर गर्व है। 2021 में कोयला उत्पादन करने के लिए कारमाइकल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी है।

16 मोबाइल भारत में बनाएंगी 10.5 लाख करोड़ स्मार्टफोन

केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रु के निवेश को दी मंजूरी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के 11,000 करोड़ रुपये के निवेश वाले 16 मोबाइल फोन विनिर्माण प्रस्तावों को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत ये कंपनियां अगले पांच साल में करीब 10.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन बनाएंगी। इनमें आईफोन बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी ''ज्ज्त की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन होन हाई, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा सैमसंग और राइजिंग स्टार के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। घरेलू कंपनियों में लावा, भगवती (माइक्रोमैक्स), पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स (डिक्सॉन टेक्नोलॉजीस), यूटीएल नियोलिंक्स और ऑप्टिमस के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत 16 योग्य आवेदकों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी.' बयान में कहा गया है कि योजना के तहत जिन कंपनियों को मंजूरी दी गई है वह अगले पांच साल में दो लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगी। जबकि इससे करीब तीन गुना अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा। मंत्रालय ने बयान में कहा, 'योजना के तहत मंजूरी पाने वाली कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में करीब 11,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश भी लाएंगी।

व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) एक अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गयी थी। बयान में कहा गया है कि योजना के तहत मंजूरी पाई कंपनियों के अगले पांच साल में 10.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन उत्पादित करने की उम्मीद है।' इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा श्रेणी में एटीएंडएस, एसेंट सर्किट्स, विजिकॉन, वालसिन, सहस्रा और नियोलिंक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।

पीएलआई योजना के तहत सरकार लक्षित श्रेणी के भारत में विनिर्मित सामान की क्रमिक बिक्री पर योग्य कंपनियों को चार से छह प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा. यह प्रोत्साहन 2019 20 को आधार वर्ष मानकर दिया जाएगा। इस योजना के तहत विदेशी कंपनियों के 15,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के मोबाइल फोन को प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। जबकि घरेलू कंपनियों के लिए इस तरह की कोई सीमा नहीं रखी गयी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि घरेलू और वैश्विक मोबाइल फोन एवं फोन उपकरण विनिर्माता कंपनियों के आवेदन करने के संदर्भ में पीएलआई योजना ने बड़ी सफलता अर्जित की है। बयान में प्रसाद के हवाले से कहा गया है, 'हम देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए मजबूत पारितंत्र और मूल्य श्रृंखला खड़ी करने को लेकर आशावान है। साथ ही इसका एकीकरण वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भी करेंगे ताकि देश में इसके विनिर्माण के माहौल को बेहतर किया जा सके।'

दशहरा और दिवाली से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को दिया तोहफा, खत्म किए ये चार्ज

नई दिल्ली। एजेंसी

बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन से पहले रिटेल लोन की पेशकश की घोषणा की है। होम लोन और कार लोन के लिए के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मौजूदा लागू दरों में 0.25 फीसदी की छूट दे रहा है। इसके अलावा, बैंक प्रोसेसिंग शुल्क भी माफ करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड और जीएम- मॉर्गिज एंड अदर एसेट्स एच टी सोलंकी ने कहा, आगामी त्योहारी सीजन के लिए इन रिटेल लोन ऑफर की शुरुआत के साथ, हम मौजूदा निष्ठावान ग्राहकों को उपहार देने का इरादा रखते हैं और साथ ही बैंक के नए ग्राहकों को कार लोन लेने पर या होम लोन की शिफ्टिंग पर आकर्षक प्रस्ताव भी देते हैं। इस ऑफर के तहत ब्याज दरें भी कम रखी गई हैं और ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस से भी छूट दी गई है।

PNB का नया ऑफर

पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव बोनांजा ऑफर लेकर आया है। PNB की ओर से जारी बयान के अनुसार, फेस्टिव बोनांजा ऑफर के तहत बैंक अपने कुछ बड़े रिटेल प्रोडक्ट जैसे कि होम लोन, कार लोन आदि पर सभी तरह के अपफ्रंट, प्रोसेसिंग चार्ज और डॉक्यूमेंट चार्ज को माफ करेगा।

ग्राहक इस ऑफर का फायदा PNB के देशभर में 10,897 शाखाओं या डिजिटल चैनल के जरिए 31 दिसंबर 2020 तक ले सकते हैं। ग्राहकों के लिए कर्ज को सस्ता और सुगम बनाने के लिए पीएनबी ने नए और टेकओवर लोन पर भी प्रोसेसिंग फीस घटा दिया है। बयान के अनुसार, होम लोन पर ग्राहकों को अब लोन की रकम का 0.35 फीसदी (अधिकतम 15,000 रुपये) और इसके अलावा डॉक्यूमेंट चार्ज से छूट मिलेगी। इसी तरह, कार लोन पर ग्राहकों को कुल लोन रकम की 0.25 फीसदी की बचत होगी। इसी तरह लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मामले पर ग्राहकों को 1 लाख रुपये तक की, लोन रकम के आधार पर, छूट मिलेगी।

भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला

ट्रेन प्रस्थान से 30 मिनट पहले जारी होगा दूसरा रिजर्वेशन चार्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रेलवे ने 10 अक्टूबर से दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार करने के लिए पहले के सिस्टम को बहाल करने का फैसला किया है। पिछले कुछ महीनों से इस सिस्टम को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोका गया था। कोविड 19 के पहले के निर्देशों के अनुसार ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान टाइम से कम से कम 4 घंटे पहले पहला आरक्षण चार्ट तैयार किया जाता था। अब पीआरएस काउंटरों के साथ-साथ दूसरे आरक्षण चार्ट तैयार होने तक पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर इंटरनेट के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। रेलगाड़ियों के प्रस्थान के निर्धारित या पुनर्निर्धारित समय से 5 मिनट से 30 मिनट पहले के बीच दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था। किराया वापसी करने के नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस अवधि के दौरान बुक की गई टिकटों को रद्द करने की भी अनुमति दी गई थी। महामारी के कारण, ट्रेनों के प्रस्थान के निर्धारित या पुनर्निर्धारित समय से 2 घंटे पहले दूसरे रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में तबदीली लाने के निर्देश दिए गए थे। रेल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जोनल रेलवे के अनुरोध के अनुसार इस मामले पर सोच विचार किया गया और यह फैसला लिया गया है कि ट्रेन के प्रस्थान के निर्धारित/पुनर्निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा।दूसरा चार्ट तैयार करने से पहले ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटर दोनों पर टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सीआरआईएस ने सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि इस प्रावधान को दिनांक 10 अक्टूबर 2020 से बहाल किया जा सके।

RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हो रही है, 09 अक्टूबर को होगा नतीजों का ऐलान

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

रिजर्व बैंक की नव-गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बुधवार को अपनी तीन-दिवसीय बैठक की शुरुआत की। समिति के बैठक के नतीजों की घोषणा शुक्रवार को होगी। समिति की यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण नीतिगत दर को यथावत रखे जाने के अनुमान हैं। एमपीसी की यह बैठक पहले 29 सितंबर से एक अक्टूबर के दौरान होने वाली थी। हालांकि नये स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण बैठक का समय नये सिरे से तय किया गया।

सरकार ने अब तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे को आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली एमपीसी का सदस्य नियुक्त किया है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में तेजी के मद्देनजर नीतिगत दर में कमी नहीं कर सकता है। हालांकि उद्योग संगठनों का विचार है कि रिजर्व बैंक को कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने की गंभीर चुनौतियों के मद्देनजर नीतिगत ब्याज दरों में कमी का अपना रुख बनाये रखना चाहिए।

यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) पिछली दो तिमाहियों (मार्च और जून 2020) में

आरबीआई के ऊपरी सीमा छह प्रतिशत से अधिक रही है। इसके सितंबर तिमाही में भी छह प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है। जैन का अनुमान है कि रिजर्व बैंक नीतिगत दर को यथावत रखेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहले कहा था, हालांकि मौद्रिक नीति से संबंधित उपाय करने का विकल्प है, लेकिन इसे आगे आ सकने वाली अप्रत्याशित परिस्थिति के लिये बचाकर रखना उचित होगा। मनीबॉक्स फाइनेंस के सह संस्थापक एवं सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मयुर मोदी ने कहा कि छोटी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को कार्यशील पूंजी तथा वृद्धि दोनों मोर्चे पर तरलता से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

रिसर्जेंट इंडिया की प्रबंध निदेशक ज्योति प्रकाश गादिया ने कहा कि आरबीआई को इस स्तर पर वृद्धि को तरजीह देना चाहिये, भले ही इसके कारण मुद्रास्फीति के मोर्चे पर कुछ कीमत चुकानी पड़े। फर्स्टरैंड बैंक के ट्रेजरी हेड हरिहर कृष्णमूर्ति ने कहा कि हर किसी के साथ, मैं भी नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे के स्तर से ऊपर है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अगस्त में हुई पिछली बैठक में नीतिगत दर को यथावत रखा था। हालांकि उससे पहले फरवरी के बाद से रिजर्व बैंक नीतिगत दर में 1.15 अंक की कटौती कर चुका है।

कोरोनरी आर्ट्री की बीमारी (सीएडी) होने में अनकंट्रोल्ड हाईपरटैंशन एक बड़ा कारण है

हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर मोनिटरिंग के ज़रिए ब्लड प्रैशर मैनेजमेंट के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है

लेखक : डॉ. शैलेंद्र त्रिवेदी
निदेशक, कार्डियोलॉजी विभाग, मेदांता अस्पताल, इंदौर
(सामान्य अवलोकन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए व्यक्त किए गए स्वतंत्र विचार हैं)

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

स्टडी के अनुसार, अनकंट्रोल हाइपर टैंशन कोरोनरी आर्ट्री की बीमारी (सीएडी) से हुई 24ङ्क मौतों का कारण रहा है । सीएडी विकसित और विकासशील, दोनों देशों में मृत्यु दर और रोगों के बढ़ने के सबसे आम कारणों में से एक है।विश्व हृदय दिवस पर, सीएडी को रोकने और उससे जुड़ी जटिलताओं से बचने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव और ब्लड प्रैशर की रेगुलर मोनिटरिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

सीएडी तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को खून पहुंचाने वाली आर्ट्री या तो कठोर हो जाती है या सिकुड़ जाती हैं।यह उनकी अंदरुनी वॉल पर कोलेस्ट्रॉल और अन्य सामग्री के जमने या बनने के कारण होता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। जैसे-जैसे यह बढ़ता है, आर्ट्री से खून बहना शुरु होता है।नतीजतन, हृदय की मांसपेशी को वह रक्त या ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जिसकी उसे जरूरत होती है। इससे सीने में दर्द (एनजाइना) या दिल का दौरा पड़ सकता है।

इस बारे में बोलते हुए, डॉ. शैलेंद्र त्रिवेदी, निदेशक-विभाग, कार्डियोलॉजी, मेदांता अस्पताल इंदौर,ने कहा,'कोरोनरी आर्ट्री रोग (सीएडी) के रोगियों के लिए, ब्लड प्रैशर को कंट्रोल में रखना ज़रुरी है।सीएडी संयोजन में, अनकंट्रोल हाइपर टैंशन, स्ट्रोक सहित विभिन्न दिल से जुड़ी समस्याओं के लिए जोखिम उठा सकता है।सांस की तकलीफ, धड़कन (अनियमित दिल की धड़कन, कंठ की धड़कन, या छाती में एक फ्लिप-फ्लॉप जैसी भावना), तेजी से दिल की धड़कन, कमजोरी या चक्कर आना, घबराहट और पसीना आना सीएडी के कुछ प्राथमिक लक्षण हैं।हृदय रोग के पारिवारिक इतिहास वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और नियमित जांच की आवश्यकता होती है। 'अनकंट्रोल हाइपर टैंशन को एंटीहाइपरटेंसिव दवाएँ लेने वालों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 स्प्यु या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm Hg के रूप में परिभाषित किया गया है।

डॉ. त्रिवेदी ने आगे कहा,'सीएडी में, हृदय तक खून रुकता है, इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।यह प्लाग टूटने से दिल का दौरा पड़ सकता है या अचानक दिल का धड़कना बंद हो सकता है।पैदा होने के समय से ही आर्ट्री में रुकावट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।हालांकि, जो चीज तेजी से बनती है वह है हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन, जीवनशैली, शारीरिक गतिविधि की मात्रा है।इन छोटी-छोटी जानकारियों पर ध्यान देना कम उम्र में ही हाई ब्लड प्रैशर और इससे जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों, दोनों को प्राप्त करने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। '

जो लोग खुद में जटिलताओं या जोखिम को बढ़ाते हैं, उन्हें तत्काल उपचार प्रदान करना अनिवार्य है।खून के बहाव को बहाल करने और सुधारने के लिए रुकी हुई या सिकुड़ी हुई आर्ट्री में एंजियोप्लास्टी की सिफारिश की जा सकती है।यह हृदय की मांसपेशियों के नुकसान को कम करने या उससे बचने में मदद करती है।यह प्रक्रिया एक लंबी, पतली ट्यूब (कैथेटर) के को धमनी के सिकुड़े हुए हिस्से में पहुंचाने से शुरु होती है।एक पतले तार की जाली (स्टेंट) को एक खंडित गुब्बारे पर लगाया जाता है और फिर कैथेटर के माध्यम से संकरे क्षेत्र में ले जाया जाता है।गुब्बारा फुलाया जाता है, आर्ट्री की वॉल के खिलाफ जमा को दबाया जाता है और विस्तारित स्टेंट को धमनी में एम्बेडेड छोड़ देते हैं।ड्रग-एल्यूटिंग स्टेंट रिलीज़ दवा को तनावग्रस्त धमनियों की पोस्ट प्रक्रिया को ठीक करने में मदद करता है।कुछ ड्रग-एल्यूटिंग स्टेंट यूएसएफडीए द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और डायबिटीज़, हाई ब्लिडिंग रिस्क या उन रोगियों में सुरक्षित उपयोग के लिए अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है, जिन्हें एंजियोप्लास्टी के एक महीने बाद दवा रोकनी पड़ सकती है।

निम्नलिखित युक्तियां सीएडी की शुरुआत को रोकने और ब्लड प्रैशर मैनेज करने में मदद कर सकती हैं।

धूम्रपान छोड़ें :धूम्रपान किसी भी हृदय रोग के खतरे को दोगुना कर देता है और इससे बचना मुश्किल हो जाता है ।

स्वस्थ भोजन खाएं:ओमेगा -3 और ओमेगा -6 फैटी एसिड से रोज़ाना कैलोरी का कम से कम 5ङ्क से 10ङ्क लेना चाहिए ।अच्छे स्रोतों में वनस्पति तेल जैसे सूरजमुखी, कुसुम, मक्का और सोयाबीन के साथ-साथ नट और बीज भी शामिल हैं।

नियमित रूप से व्यायाम करें:दिल और समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रति दिन लगभग 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि ज़रुरी है।

तनाव कम करना:योग और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का सहारा लेंजो अच्छे स्ट्रेस बस्टर के रूप में कार्य करते हैं।

साधारण पारिवारिक पेंशन पर सरकार का बड़ा फैसला

7 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्यता खत्म

नई दिल्ली। एजेंसी

मोदी सरकार ने रक्षाकर्मियों को बड़ी राहत दी है। रक्षा मंत्रालय ने मृत रक्षाकर्मियों के परिजनों के लिए बढ़ी हुई साधारण पारिवारिक पेंशन (EOFP) के लिए लगातार 07 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ध्ङ्क रक्षाकर्मी के पिछले वेतन का 50% होती है और यह सेवा के दौरान रक्षाकर्मी (Defence Personnel) की मृत्यु की तारीख से 10 साल के लिए देय होती है। मंत्रालय ने कहा कि EOFP प्राप्त करने के लिए लगातार 07 साल की सेवा अनिवार्यता 1 अक्टूबर 2019 से खत्म कर दी गई है। इसमे बताया गया कियदि नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट, डिस्चार्ज के बाद सेवाकर्मी की मौत हो जाती है तो उसकी मौत से 7 साल तक के लिए या उस समय तक जब कर्मी 67 साल का होता, जो भी पहले हो, तक के लिए EOFP दी जाती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिन रक्षा कर्मियों की मृत्यु लगातार 07 साल की सेवा होने से पूर्व 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के भीतर हुई है, उनके परिजनों को अब EOFP मिलेगी। अब तक रक्षा बलों के कर्मियों के परिजनों को EOFP देने के लिए संबंधित रक्षाकर्मी की लगातार 07 साल की सेवा पूरी होने का नियम था, लेकिन अब यह जरूरत समाप्त कर दी गई है। बढ़ी हुई साधारण पारिवारिक पेंशन (EOFP) जहां सशस्त्र बल के कर्मी के पिछले वेतन की 50 प्रतिशत है, वहीं साधारण पारिवारिक पेंशन (ओएफपी) कर्मी के पिछले वेतन की 30 प्रतिशत होती है। रक्षा कर्मियों की सेवा समाप्ति / सेवानिवृत्ति / निर्वहन / अमान्य होने के समय पेंशन की उपलब्धता रहेगी तो बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन, मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रदान की जाती है, जो भी पहले हो।

टीवी विनिर्माताओं को बड़े आकार के प्रीमियम सेट आयात करने की मंजूरी मिली

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने सैमसंग, एलजी और सोनी जैसे प्रमुख टेलीविजन विनिर्माताओं को पहले से तैयार टीवी सेट के आयात का लाइसेंस दिया है। टीवी उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है, क्योंकि त्योहारी मौसम में मांग गति पकड़ रही है। ये टीवी विनिर्माता महंगे प्रीमियम श्रेणी के टेलीविजन सेट के लिए आयात पर निर्भर हैं। कई कंपनियां 55 इंच या उससे बड़ी स्क्रीन वाले टेलीविजन सेट का आयात करती हैं। सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नैय्यर ने बताया, ''हमारे बड़ी स्क्रीन वाले टेलीविजन बंदरगाहों पर अटक गए थे, लेकिन अब हमें सरकार से लाइसेंस मिल गया है।'' सरकार के इस फैसले के बाद बाजार में प्रीमियम टीवी सेट की उपलब्धता बढ़ जाएगी और त्योहारी सीजन के दौरान मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। दक्षिण कोरियाई विनिर्माता एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी लाइसेंस मिलने की पुष्टि की है। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, ''हमें सरकार से लाइसेंस मिल गया है और हमारी खेप जारी कर दी गई है।'' सूत्रों के अनुसार दक्षिण कोरियाई विनिर्माता सैमसंग को भी टीवी सेट के आयात के लिए लाइसेंस मिल गया है और इससे कंपनी बंदरगाहों पर फंसी खेप को बाजार में ला सकेगी।

कंटेनर की उपलब्धता नहीं होना निर्यात क्षेत्र के लिये वर्तमान में एक चुनौती

नयी दिल्ली। एजेंसी

निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो ने बुधवार को कहा कि निर्यात क्षेत्र में कंटनेर की उपलब्धता नहीं होना अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। कंटेनर नहीं मिलने से निर्यात दायित्वों को समय पर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। निर्यातकों के संगठन 'फैडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से तीन से चार सप्ताह पहले जगह देने की पेशकश करने के बाद जहाजरानी कंपनियां कंटेनर को यह कहते

हुये अचानक बंद कर देती हैं कि जलयान में जगह नहीं बची है। उन्होंने यह भी कहा कि जुलाई के बाद से समुद्री रास्ते से माल भेजने के भाड़े में वृद्धि होने लगी है। जहाजी कंपनियों ने भाड़े गंतव्य स्थल के हिसाब से 20 से लेकर 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं। सराफ ने कहा कि जहाजरानी क्षेत्र के लिये एक नियामकीय एजेंसी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स उत्कर्ष पूर्वानुमेयता और सुरक्षा (एनएलईएपीएस) कानून को तैयार किया जायेगा और आयात-निर्यात क्षेत्र को इस तरह के अचानक होने वाले बदलावों से बचाने के लिये जल्द से जल्द लागू किया जायेगा।'' उन्होंने कहा कि निर्यात कारोबार में तेजी आने लगी है ऐसे में निर्यात कारोबार से जुड़ी तमाम साजोसामान की सुविधाओं की तरफ ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे निर्यातकों के समक्ष जो नये अवसर सामने आये हैं उनका लाभ वह नहीं उठा पायेंगे।

नवरात्रि : शरीर के 9 छिद्र और 9 संयम, जानिए व्रत में क्यों हैं जरूरी

हिन्दू धर्म में वर्ष में चार नवरात्रियां आती हैं। माघ, चैत्र, आषाढ और अश्विन माह। चैत्र माह की नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। बाकी बची दो आषाढ़ और पौष-माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। चार नवरात्रियों में कुल 36 दिन होते हैं। इन दिनों में शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र और शुद्ध बने रहने की जरूर होती है।

9 छिद्र

हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं। दो आंख, दो कान, नाक के दो छिद्र, दो गुप्तांग और एक मुंह। उक्त नौ अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्री को जाग्रत करेगा। नींद में यह सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जाग्रत रहता है। वर्ष की 36 नवरात्रियों में उपवास रखने से जहां अंग-प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है वहीं मन में पवित्रता का जन्म होता है।

9 संयम

इन नौ दिनों में कम से कम 9 तरह के संयम की जरूरत होती है।

1. आहार संयम : इसमें मांस-भक्षण करना, तामसिक और राजसी भोजन करना वर्जित है। सात्विक भोजन एक समय का कर सकते हैं अन्यथा फलाहार ही लें।
2. मद्यमान : इन दिनों में किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकते हैं। जैसे मद्यपान, सिगरेट, तम्बाकू आदि।
3. स्त्रिसंग शयन : इन दिनों में यह कार्य करना पाप माना जाता है।
4. नकारात्मक विचार : यह पवित्र दिन होते हैं। इन दिनों में पूरे नौ दिनों तक माता की भक्ति में ही रहने से किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं आते हैं।
6. वाणी संयम : कई लोग इन 9 दिनों मौन रहते हैं। मौन नहीं रह सकते हैं तो कम से कम मुंह से किसी भी प्रकार के कटु वचन, बुरे वचन या गाली आदि का प्रयोग नहीं किया जाता।
7. मानसिक संयम : नौ दिनों में क्रोध, मद, लोभ, आसक्ति, रोना, हंसना और अन्य किसी भी प्रकार के उद्वेगपूर्ण भाव रखना नहीं चाहिए। मन को काबू में रखें।
8. वर्जित साधनाएं : कई लोग इन नौ दिनों में तांत्रिक साधना या अन्य तरह की अघोर साधना करते हैं जो कि सामान्य लोगों के लिए वर्जित है।
9. गलतियों से बचें : यदि आप माता की साधना, पूजा आदि करना नहीं जानते हैं तो भक्ति ही सर्वोपरि है। आप इन गलतियों से बचें। पूजा-पाठ में गलतियां न हो इसका ध्यान रखें। पूजा स्थल और घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।

व्रत रखने वाले व्यक्ति को गंदे या बिना स्नान किए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि व्रत के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए। खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली का सेवन करें। अगर दुर्गा चालीसा, मंत्र, सप्तशती पाठ या चण्डी पाठ पढ़ रहे हैं तो इसके नियमों का पालन करें। पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बात न करें। नवरात्रों में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए।

इस साल क्यों खास है नवरात्रि का त्यौहार

मां की आराधना हर रूप में भक्तों को सुख देने वाली होती है लेकिन शारदीय नवरात्र शक्ति पर्व इस बार भक्तों के लिए साधना का विशेष अवसर लेकर आ रहा है। जानकारों का कहना है कि वर्ष 2020 की शारदीय नवरात्री में पूजा उत्सव के साथ साधना के विशेष दिनों में भक्त मां की आराधना करके समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं।

ये हैं नवरात्रि के विशेष फलदायी दिन

नवरात्रि शनिवार 17 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक है। इस दौरान हर दिन विशेष शक्ति आराधना से विशेष लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। अमेरिका में रह रही इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन की चैप्टर चेयरपर्सन और टैरो कार्ड रीडर भूमिका कलम का कहना है कि जो लोग पुरे 9 दिन उपवास या साधना ध्यान या दान न कर पाएं वे भी इन विशेष दिनों में लाभ ले सकते हैं।

17, 19, 23 और 24 अक्टूबर मन्त्र साधना के लिए सबसे उत्तम दिन हैं। इन दिनों में मन्त्रों को सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि सर्वार्थसिद्धि योग बन रहा है।

18 और 24 अक्टूबर को सिद्धि महायोग बनने के कारण ध्यान साधना से माता को प्रसन्न करें। यह गृहस्थ जनों को समृद्धि देने वाला समय होगा।

जिनके रिश्तों में कड़वाहट भर रही है, वे 18 और 19 अक्टूबर को प्रीति योग में मां को शहद अर्पित कर किसी जरूरतमंद को दान करें।

21 अक्टूबर को ललिता पंचमी के दिन हर तरह से समृद्धि के लिए मां की अर्चना करें और ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें।

अलग-अलग समस्याओं के लिए हैं ये आसान उपाय

1. यदि आप क़र्ज़ की परेशानी के चलते परेशान हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से अंतिम दिन तक लगातार मंगल ऋणमोचक स्त्रोत का पाठ करें।
2. यदि आप किसी पुरानी बीमारी के चलते परेशान चल रहे हैं तो नवरात्रि राम रक्षा स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से प्रारंभ कर दें।
3. स्थाई लक्ष्मी निवास के लिए नवरात्रि मे श्रीसूक्त का पाठ तुरंत असरदायी होता है।
4. जो जातक राहु, केतु और शनि ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, उनके लिए नवरात्रि मे माता काली की साधना लाभदायक होगी।
5. नवरात्रि मे देवी के अथर्वशीर्ष का पाठ करने से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है।
6. अगर आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है तो माता के मंदिर मे नवरात्रि के नौ दिन तक लगातार माता पार्वती और भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करने से शांति मिलेगी।
7. मनवांछित विवाह के लिए नवरात्रि में भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें तथा माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करें।
8. यदि आपके आस पास नकारात्मक उर्जा है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि मे भैरव मंदिर मे दीप दान करें।
9. यदि धन की कमी से परेशान हैं तो नवरात्रि के पहले दिन 11 लघु नारियल एक लाल कपड़े को बिछाकर उस पर रख दें और नौ दिन तक उनकी पूजा करें। फिर नवरात्रि के आखिरी दिन उसे अपने धन स्थान पर रख दें। इससे लक्ष्मी का स्थाई वास होगा और धन से जुड़ी समस्या भी दूर होगी।
10. जो लोग संतान सुख से को लेकर चिंतित हैं, वे नवरात्रि मे माता भुवनेश्वरी की पूजा उपासना करें।

नवरात्रि पर दुर्गा पूजन का कार्यक्रम

पंचांग के अनुसार नवरात्रि का पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होगा, जो 17 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन सूर्य कन्या राशि में चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन घटस्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजकर 23 मिनट से प्रातः 10 बजकर 12 मिनट तक है।

नवरात्रि का तिथि वार पूजा कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा-

- **17 अक्टूबर:** प्रतिपदा घटस्थापना
- **18 अक्टूबर:** द्वितीया मां ब्रह्मचारिणी पूजा
- **19 अक्टूबर:** तृतीय मां चंद्रघंटा पूजा
- **20 अक्टूबर:** चतुर्थी मां कुष्मांडा पूजा
- **21 अक्टूबर:** पंचमी मां स्कंदमाता पूजा
- **22 अक्टूबर:** षष्ठी मां कात्यायनी पूजा

23 अक्टूबर: सप्तमी मां कालरात्रि पूजा

24 अक्टूबर: अष्टमी मां महागौरी दुर्गा महा नवमी पूजा दुर्गा महा अष्टमी पूजा

मंडियों में उतरा अफगानी प्याज, दिल्ली में दाम में आई नरमी

नई दिल्ली। एजेंसी

अफगानी प्याज के उत्तर भारत की मंडियों में उतरने से पहले देश की राजधानी दिल्ली में प्याज के दाम में नरमी आ गई है। दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में प्याज के थोक भाव में दो से तीन रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। अमृतसर के प्याज कारोबारी गौरव ने बताया कि अफगानिस्तान से चली प्याज की बोर्डर पर आ चुकी है, लेकिन मंडियों में अफगानी प्याज के उतरने में अभी दो दिन और लगेंगे। आजादपुर मंडी के कारोबारी बताते हैं कि मंडी में प्याज की आवक में सुधार हुआ है और मौजूदा भाव पर जितनी मांग है, उतनी आपूर्ति होने लगी है। कारोबारियों की मानें तो अफगानी प्याज आने के साथ-साथ घरेलू आवक भी आने वाले दिनों में बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि राजस्थान में प्याज की नई फसल उतर गई है जिससे कीमतों में और गिरावट आ सकती है। आजादपुर कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) की रेट लिस्ट के अनुसार, शनिवार को मंडी प्याज का थोक भाव 12.50 रुपये प्रति किलो से 40 रुपये प्रति किलो था जो सोमवार को घटकर 12.50 रुपये से लेकर 37.50 रुपये प्रति किलो पर आ गया। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में प्याज के खुदरा भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी उपभोक्ताओं को 40 से 50 रुपये किलो प्याज खरीदना पड़ रहा है महाराष्ट्र की प्रमुख प्याज मंडी लासल गांव में सोमवार को प्याज का थोक भाव 800 रुपये से 3921 रुपये प्रतिक्विंटल था।आजादपुर मंडी पोटैटो ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन यानी पोमा के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान की अलवर मंडी में प्याज की नई फसल उतर गई है और दिल्ली में भी आने वाले दिनों में नई फसल कील आवक बढ़ने वाली है। उन्होंने बताया कि इस समय दिल्ली में राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात से भी प्याज की आवक हो रही है और मौजूदा भाव पर जितनी मांग है, उसके अनुरूप आपूर्ति होने लगी है, इसलिए कीमतों में तेजी पर ब्रेक लग गया है। आजादपुर एपीएमसी के आंकड़ों के अनुसार, मंडी में रविवार को प्याज की आवक 1,083.5 टन थी और सोमवार को भी आवक 285.2 टन दर्ज की गई।शर्मा ने कहा कि अफगानी प्याज दिल्ली की मंडियों में उतरने में अभी देर है, लेकिन उससे पहले घरेलू आवक बढ़ने लगी है, जो खुशी की बात है। कारोबारी बताते हैं कि अफगानी प्याज की मांग उसकी क्वालिटी पर निर्भर करेगी। अमृतसर के कारोबारी गौरव ने कहा कि अफगानिस्तान से आने वाले प्याज की क्वालिटी के साथ-साथ, आयात का खर्च को भी जोड़कर देखा जाएगा कि मौजूदा भाव पर मंगाने में फायदा है या नहीं।

कच्चे माल की कम लागत से भारत के सूती धागे का निर्यात लाभ में रहेगा: रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

भारतीय कपास की चीन में बिक्री में लगभग 20 प्रतिशत तक की गिरावट आने के बावजूद देश कम लगात के अपने इस माल और अमेरिका में अपने कपड़ा कारोबारियों की मौजूदगी का लाभ उठा सकता है।इंडिया रेटिंग की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सूती-धागा कारोबारी चीन के बाजार पर कुछ अधिक ही निर्भर हैं। चीन को सूती धागे का निर्यात, जून 2020 में समाप्त हुई तीन महीनों में, कमजोर मांग तथा वियतनाम और पाकिस्तान से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण लगभग 20 प्रतिशत तक कम हो गया। हालाँकि, व्यापार-युद्ध (अमेरिका और चीन के बीच) के विस्तार और श्रम-संबंधी मुद्दे पड़ोसी देशों से अतिरिक्त यार्न और कपास की मांग के कारण निर्यात बढ़कर पांच लाख टन और 80 से एक करोड़ गांठ की हो साकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और ब्राजील जैसे देशों को चीनके बाजार में तरजीह मिलती है। लेकिन, भारत कम लागत वाली कच्चे माल की उपलब्धता और अमेरिका में भारतीय कपड़ा व्यापारियों की मौजूदगी को देखते हुए, लाभ कमा सकता है।

भारत में डेटा विज्ञान क्षेत्र में 93,500 से अधिक पद रिक्त: अध्ययन

बेंगलुरू। एजेंसी

भारत में डेटा विज्ञान क्षेत्र में अगस्त 2020 के अंत तक 93,500 से अधिक पद रिक्त थे। शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ग्रेट लर्निंग के एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आयी है। कंपनी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बाद भी विश्लेषण से संबंधित कार्यों को लेकर आशा व उम्मीदें कायम हैं। इस साल जनवरी में इस क्षेत्र के कुल वैश्विक रोजगार में भारत जहां 7.2 प्रतिशत का योगदान दे रहा था, वहीं भारत का योगदान अगस्त 2020 के अंत तक बढ़कर 9.8 प्रतिशत पर पहुंच गया। अध्ययन के अनुसार, भले ही इस क्षेत्र में रिक्तियां फरवरी 2020 के 109,000 से कम होकर मई 2020 में 82,500 पर आ गयी हों, इसमें मांग लगातार बनी हुई है। कंपनी ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) व केपीओ क्षेत्र मांग की अगुवाई कर रहा है।

एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर, नया रेकॉर्ड बना सकता है चावल का निर्यात

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना काल में कृषि और निर्यात के मोर्चे पर अच्छी खबर है। इस साल चावल का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 42 फीसदी बढ़कर नया रेकॉर्ड बना सकता है। चावल निर्यात करने वाले बाकी देशों से कम एक्सपोर्ट और रुपये की कीमत में कमी के कारण भारत से निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है।

Rice Exporters Association के प्रेजिडेंट बी वी कृष्ण राव ने कहा कि 2020 में देश से चावल का निर्यात 1.4 करोड़ टन पहुंच सकता है। पिछले साल यह 99 लाख टन था जो 8 साल में सबसे कम था। उन्होंने कहा, 'थाईलैंड में सूखा पड़ने के कारण वहां से निर्यात घट रहा है। कम फसल होने का कारण वियतनाम संघर्ष कर रहा है। जाहिर है कि उनकी भरपाई भारत करेगा।'

थाईलैंड में सूखा

थाईलैंड चावल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस साल सूखे के कारण वहां धान की फसल प्रभावित हुई है। इस साल वहां से निर्यात गिरकर 65 लाख टन रहने की उम्मीद है जो 20 साल मे सबसे कम है। इसी तरह चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक वियतनाम मीकोंग डेल्टा में जल स्तर की कमी से जूझ रहा है। यह डेल्टा देश का सबसे बड़ा धान उत्पादक इलाका है। इस कारण वियतनाम से भी इस बार चावल के निर्यात में कमी आना तय है।

भारत मुख्य रूप से बांग्लादेश, नेपाल, बेनिन और सेनेगल को गैर-बासमती चावल का निर्यात करता है। बासमती चावल का निर्यात मुख्य रूप से ईरान, सऊदी अरब और इराक को होता है। ओलम इंडिया के राइस बिजनेस के वाइस प्रेजिडेंट नितिन गुप्ता ने कहा कि अफ्रीकी देशों से गैर बासमती चावल की मांग बढ़ने से इस साल भारत का निर्यात बढ़ेगा। उन्होंने कहा, 'बासमती चावल के निर्यात में एक तरह से ठहराव आ गया है लेकिन आकर्षक कीमतों के कारण गैर-बासमती चावल की मांग बहुत बढ़ी है। गैर-बासमती चावल का निर्यात दोगुना होकर 95 लाख टन पहुंच सकता है। बासमती चावल का निर्यात करीब 45 लाख टन रहने का अनुमान है।'

बीते पखवाड़े में 25 रुपए किलो महंगी हुई तुअर दाल

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की प्रमुख मंडियों में तुअर की आवक घटने से दाल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। बीते एक पखवाड़े में तुअर दाल 25 रुपये प्रति किलो से ज्यादा महंगी हो गई है और आपूर्ति में कमी की वजह से दाम में और इजाफा होने की संभावना बनी हुई है। तुअर दाल का थोक भाव यानी एक्स-मिल रेट मंगलवार को 115 रुपये प्रति किलो था। ऑल इंडिया दाल मिल एसोएिशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि बीते एक पखवाड़े में तुअर दाल के दाम में 25 से 30 फीसदी का इजाफा हुआ है। वहीं, तुअर का खुदरा भाव इस समय 120 रुपये से 140 रुपये प्रति किलो चल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में खुदरा भाव और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। अग्रवाल ने कहा कि त्योहारी सीजन से पहले तुअर की आपूर्ति का टोटा पड़ने से दाम बढ़ने की संभावना से सरकार को अवगत करवाते हुए, कई बार पत्र लिखकर आयात के लिए लाइसेंस जारी करने की गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस साल चार लाख टन तुअर आयात का कोटा तय किया है, मगर आयात के लिए लाइसेंस अब तक जारी नहीं किया गया। कारोबारी बताते हैं कि तुअर के दाम में तेजी पर लगाम दो ही सूरत में लग सकती है। पहली, यह कि सरकारी एजेंसी नेफेड के स्टॉक में पड़ा तुअर (कच्चा) बाजार में उतारा जाय, या फिर तुअर आयात के लिए लाइसेंस जारी किया जाए।

इंडिया पल्सेस एंड ग्रेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतू भेडा ने कहा कि नेफेड के पास इस समय आठ लाख टन तुअर का स्टॉक है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि सरकार इसमें से कितना बफर स्टॉक रखेगी और कितना बाजार में उतारेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नेफेड का पूरा स्टॉक निकाल देती है, तो फिर दाम में तेजी पर लगाम लग जाएगी। इसके अलावा, आयात के लिए अगर लाइसेंस जारी करती है, तो भी कीमतों में नरमी आ जाएगी।

आईपीजीए के अध्यक्ष ने बताया कि तुअर की नई फसल दिसंबर से पहले नहीं आने वाली है और तुअर की औसत खपत करीब तीन लाख टन होती है, ऐसे में नई फसल आने तक करीब नौ लाख टन तुअर की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए अगर आयात की अनुमति नहीं मिलती है, तो सरकार को अपना पूरा स्टॉक निकालना होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी फसल वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान में खरीफ सीजन में तुअर का उत्पादन 40 लाख टन होने का आकलन किया गया है। दलहन बाजार के जानकार अमित शुक्ला कहते हैं कि तुअर के दाम में नरमी तभी आएगी जब आपूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन की मांग जोरों पर होगी। बाजार सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, मंडियों में लेमन तुअर (वर्मा से आयातित) 74 रुपये प्रति किलो, जबकि देसी तुअर 83 रुपये प्रति किलो है। शुक्ला ने बताया कि, 'कर्नाटक में हुई भारी बारिश से फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है और तुअर की फसल इस बार विलंब से बाजार में आ सकती है, क्योंकि कई जगहों पर अभी तुअर में फूल ही लगा है। उन्होंने हर नवंबर के आखिरी पखवाड़े में तुअर की आवक शुरू हो जाती थी, मगर इस साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक आवक शुरू हो सकती है।

दिनेश कुमार खारा SBI चेयरमैन नियुक्त, चुनौतीपूर्ण होगी नई जिम्मेदारी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार खारा को देश के सबसे बड़े बैंक का चैयरमैन नियुक्त किया। उन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली। रजनीश कुमार ने मंगलवार को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा किया।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को तीन साल के लिए एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया। पिछले महीने बैंक के बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने खारा के नाम की सिफारिश एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में की थी।

परंपरा के अनुसार एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति बैंक में सेवारत प्रबंध निदेशकों के समूह से की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि खारा 2017 में भी चेयरमैन पद के दावेदारों में शामिल थे। खारा को अगस्त 2016 में तीन साल के लिए एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें प्रदर्शन की समीक्षा के बाद 2019 में दो साल का सेवा विस्तार मिला।

वैश्विक बैंकिंग प्रभाग के प्रमुख रहे

खारा दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से पढ़े हैं और अब तक एसबीआई के वैश्विक बैंकिंग प्रभाग के प्रमुख थे। उनके पास बोर्ड स्तर का पद है और वे एसबीआई की गैर-बैंकिंग सहायक कंपनियों के कारोबार का निरीक्षण भी करते थे। खारा प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने से पहले एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईएमएफ) के एमडी और सीईओ थे। खारा 1984 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे और उन्होंने अप्रैल 2017 में एसबीआई के पांच सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक के एसबीआई में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नए एसबीआई चेयरमैन के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्यकाल होगा, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण बैंकिंग क्षेत्र एक बड़े संकट से गुजर रहा है।

श्रीराम सुपर 111 गेहूँ बीज से किसानों की गेहूँ उत्पादकता बढ़ी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की युनिट श्रीराम फार्म सोल्यूशन्स की ओर से पेश किए गए श्रीराम सुपर 111 सीड से उनकी गेहूँ उत्पादकता बढ़ी है। श्रीराम फार्म सोल्यूशन्स ने किसानों की फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक एवं अनुसंधान-उन्मुख प्रोडक्ट विकसित किए हैं। यह बात मध्यप्रदेश के किसानों ने कही। लॉन्च के बाद से ही श्रीराम सुपर 111 गेहूँ बीज मध्यप्रदेश के किसानों में बेहद लोकप्रिय हो रहा है। श्रीराम फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स के विश्वविख्यात गेहूँ वैज्ञानिकों द्वारा इस किस्म को तैयार किया गया है।

गेहूँ की अन्य किस्मों की तुलना में बेहतरीन उत्पदकता के चलते श्रीराम सुपर 111 गेहूँ बीज किसानों में बेहद लोकप्रिय हो रहा है। इसका दाना बड़ा और चमकदार होता है, इससे चारा भी ज़्यादा मिलता है, साथ ही इस गेहूँ से बनी 'चपाती बहुत अच्छी गुणवत्ता की होती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते श्रीराम सुपर 111 गेहूँ बीज राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात के किसानों की पहली पसंद बन गया है। मध्यप्रदेश के खरगांव ज़िले से एक अनुभवी किसान विजय पटेल पिछले 4 सालों से श्रीराम सुपर 111 गेहूँ बीज बो रहे हैं। पिछले साल उन्होंने अपनी 12 एकड़ ज़मीन में यही किस्म बोई और उनके खेत की औसत उत्पादकता 25 क्विंटल प्रति एकड़ रही।

इस उत्पादन से वे बेहद खुश हैं क्योंकि उनके खेत की उत्पादकता अन्य किस्मों की तुलना में तकरीबन 3-4 क्विंटल/ एकड़ अधिक है। इससे उनका मुनाफ़ा रु 8000 प्रति एकड़ बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि इस किस्म में बाली की लंबाई और दानों की संख्या अधिक होती है (हर बाली पर 75-90 दाने)। उनका कहना है कि श्रीराम सुपर 111 उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों के नज़रिए से बेहतर है। श्रीराम सुपर 111 गेहूँ बीज बोने वाले मध्यप्रदेश के अन्य किसान भी इसी तरह की कामयाबी हासिल कर रहे हैं। भोपाल से एक और किसान तीर्थराज श्रीवास्तव पिछले 5 सालों से अपनी ज़मीन में श्रीराम सुपर 111 बो रहे हैं। वे कई किस्में उगा कर देख चुके हैं लेकिन उन्हें ऐसा उत्पादन कभी नहीं मिला। पिछले सीज़न उनकी उत्पादकता 30 क्विंटल प्रति एकड़ रहीं जो इस क्षेत्र की अन्य लोकप्रिय किस्मों की तुलना में 5-6 क्विंटल प्रति एकड़ अधिक है। उन्होंने बताया कि इसका दाना बड़ा और चमकदार

है और वे इस बात से भी खुश थे कि चमकदार दाना होने के कारण श्रीराम सुपर 111 गेहूँ को मंडी में खूब पसंद किया गया। श्रीराम सुपर 111 मध्यप्रदेश के किसानों की पहली पसंद बन गया है। श्रीराम फार्म सोल्यूशन्स के अन्य प्रोडक्ट जैसे श्रीराम सुपर 252 और श्रीराम सुपर 303 भी पिछले कुछ सालों से अपने शानदार परफोर्मेन्स के चलते किसानों में बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं।

नए कृषि कानून का दिखने लगा असर

दूसरे राज्यों से धान की खरीद पर हरियाणा में बड़ा फैसला

नई दिल्ली। एजेंसी

नया कृषि कानून (Farm Act-2020) लागू होने के बाद किसानों को कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी मिल गई है। न चाहते हुए भी इसी मजबूरी में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य से बाहर के किसानों का भी धान खरीदने की अनुमति दे दी है। यानी यानी यहां की मंडियों में अब यूपी, राजस्थान और दिल्ली के किसान भी अपनी फसल सरकारी रेट पर बेच सकते हैं। इसके लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है। इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हरियाणा के किसान भी अपनी फसल बेच पाते हैं। पिछले दिनों यूपी के कुछ किसानों को हरियाणा की करनाल मंडी में जाने से रोक दिया गया था। इसके बाद विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया था समझा जाता है कि फजीहत से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। हरियाणा सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह यह निर्णय राज्य की विभिन्न मंडियों के आढ़तियों और प्रदेश से बाहर के किसानों की मांग के चलते लिया गया है। इससे धान खरीद सीजन के दौरान दूसरे राज्यों के किसानों को अपनी फसल बेचने में मदद मिलेगी।

यहां कितनी होती है धान की खरीद?

हरियाणा और पंजाब में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक खरीद होती है। ऐसे में अब कम से कम यूपी के किसान यहां आसानी से अपनी उपज बेचकर चले जाएंगे। एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक धान खरीद की बात करें तो 2019-20 में यहां 64.23 लाख मिट्रिक टन की खरीद हुई। अब दूसरे राज्यों से धान आना शुरू होगा तो सरकार को पहले से अधिक खरीद करनी पड़ेगी। जिसका भार यहां के रेवन्यू पर पड़ेगा।

दूसरे राज्यों में फसल बेचने से रोके न जाएं किसान

किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि ना ना करते-करते कहीं न कहीं मनोहर सरकार ने नए कृषि कानून के दबाव में यह फैसला लिया है। दूसरे राज्यों के किसानों को इससे फायदा मिलेगा। अब कहीं भी फसल बेचने का कानून बन ही गया है तो सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसानों को बार-बार किसी बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा। पुलिस वाले किसी किसान भाई को दूसरे राज्य में फसल ले जाने पर परेशान न करें।

ये होगा खरीद का नियम?

हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने बताया कि किसानों को अपने साथ इस आशय के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां लानी चाहिए कि उन्होंने मालिक या किराएदार के तौर पर अपने खेतों में धान की फसल बोई है। इससे व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी में कमी आएगी।

कितनी हुई खरीद?

हरियाणा में 26 सितंबर से खरीद जारी है। यहां की मंडियों में 6 अक्टूबर तक 17,85,582 क्विंटल धान पहुंचा है। जिसमें से 1,02,003 क्विंटल की खरीद हो गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि धान की फसल के अलावा 84,930 क्विंटल बाजरे की आवक हुई है, जिसमें से 31,999 क्विंटल की खरीद हुई है। इसी तरह 1,351 क्विंटल मक्का की आवक हुई, जिसमें से 224 क्विंटल की खरीद की गई है।

त्यौहारी सीजन में नई भर्ती करेगा अमेजन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नीएल्सन द्वारा 17 शहरों में किये गए सर्वे ने बताया कि अमेज़न सेलर्स इस फेस्टिव सीजन में कर्मचारियों की नई भर्ती करने के लिए हायरिंग, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा इंफ्रा सपोर्ट और नए प्रॉडक्ट लॉन्च में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। अपने बिजनेस फिर से बहाल करते हुए सेलर्स को अधिक बिक्री होने और नए ग्राहकों तक पहुंचने की उम्मीद पिछले 9 महीनो में में Amazon.in पर सेलर्स की कुल संख्या 5.5 लाख से बढ़कर 6.5 लाख हो गई है। अमेज़न ने आज कंपनी के एक विशेष सर्वे के निष्कर्षों को साझा किया। यह सर्वेक्षण आने वाले फेस्टिव सीजन से अमेज़ॅन पर बिक्री करने वाले एसएमबी (एसँ) सेलर्स की उम्मीदों, और इसके लिए की जाने वाली तैयारी का अनुमान लगाना शामिल है। यह अध्ययन 2000 से अधिक अमेज़न सेलर्स के बीच नीएल्सन द्वारा 12-22 सितम्बर 2020 के दौरान किया गया था। पूरे भारत के 17 शहरों में, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में किये गये, इस अध्ययन में दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, लुधियाना, इंदौर, नागपुर, कोयम्बटूर, कोच्चि, पटना, जयपुर और राजकोट के सेलर्स शामिल थे। सर्वे में शामिल 98३ सेलर्स (2036) फेस्टिव सीजन के दौरान ई-कॉमर्स का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। विनोद कुमार, प्रेसिडेंट - इंडिया एसएमई फोरम ने बताया कि 'नीएल्सन का सर्वे वही बात कहता है जिस पर हम पिछले 4 महीनों से जोर दे रहे थे, यानी एमएसएमई के लिए डिजिटल सशक्तीकरण का महत्व। उनमें से कई एमएसएमईके लिए आने वाले फेस्टिव सीजन काफी बढ़ावा देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि सुरक्षित खरीदारी और व्यापक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए, वे पहली बार ईकॉमर्स जैसे माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। हमारा मानना है कि अधिक से अधिक ग्राहकों द्वारा सुरक्षित रूप से ऑनलाइन खरीदारी पसंद किये जाने के कारण; उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आकर्षित करने में एमएसएमई कीक्षमता, कोविड के पहले के स्तर वाले रोजगार को बहाल करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी और सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।'

भारत-कनाडा के बीच कृषि व्यापार की अपार संभावनाः तोमर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि भारत और कनाडा के बीच कृषि व्यापार में वृद्धि की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत-कनाडा बिजनेस चैंबर (आईसीबीसी) द्वारा आयोजित एक वेब गोष्ठी के उद्घाटन भाषण में यह बात कही। भारत और कनाडा के बीच कृषि-व्यापार में तेजी से वृद्धि का हवाला देते हुए तोमर ने कहा कि भारत कनाडा की सब्जियों और कृषि सामग्रियों का पांचवां सबसे बड़ा आयातक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार में वृद्धि की काफी अधिक संभावनाएं हैं। तोमर ने कहा कि सरकार ने 'एक देश- एक बाजार' की स्थापना और छोटे तथा सीमांत किसानों की सुरक्षा के उचित उपायों के साथ खेती में ठेका प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष भी स्थापित किया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।